

□□□□□□□□□□□□ □□□□

जनसत्ता 5 मई, 2014 : योजना आयोग के अनुसार आज भी देश में 21.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

शहर में जो आदमी □ कमीने में □ कहजार रुप□ और गांव में आठ सौ सोलह रुप□ से कम कमाता है, वह गरीबी रेखा से नीचे है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब सवा अरब की आबादी में सत्ताईस करो□ से ज्यादा ऐसे गरीब हों, जो दो जून की रोटी के जुगा□ में अपनी जदिगी होम कर रहे हों, तो उनके चुनाव में ख□ होने की कल्पना करना परहास ही होगा। अब उस आबादी की बात, जिसे सरकार खुशहाल मानती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-2006) के अनुसार, देश में छह से पैंतीस माह आयुवर्ग के 78.9 प्रतिशत बच्चे और पंद्रह से उनचास वर्ष आयुवर्ग की 56.2 फीसद महिला□ खून की कमी से पी□ ति है। ताजा जनगणना के आंक□ बताते हैं कि भारत के 53.1 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है और जहां है वहां सैतालीस फीसद में पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इन्हत्तर प्रतिशत घरों की छत कंक्रीट नहीं, मट्टी-घास या टाइल से बनी है। 52.5 प्रतिशत घरों की दीवारें रूइंट नहीं, पत्थर-मट्टी या घास से बनी है और 37.1 फीसद घर केवल □ कमरे के हैं। सत्तर प्रतिशत से ज्यादा घरों का चूल्हा लक□ी, गोबर के उपलों या मट्टी के तेल से जलता है। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खुले में नहाने के मजबूर है।

मामूली समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि अगर कोई संपन्न होगा तो खुले में शौच नहीं जा□ गा, आसमान के नीचे नहीं नहा□ गा, कच्चे घर में नहीं रहेगा और खाना बनाने के ल□ गैस के बजाय उपले या लक□ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने बच्चों और बीबी की खून की कमी या कुपोषण जैसी जानलेवा कमजोरी तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे करो□ों लोग अगर चाहें भी तो चुनाव नहीं ल□ सकते।

ताजा चुनाव में जसि हसिाब से पैसे की नदियां बही है, वह देख कर कहा जा सकता है कि इस बार लगभग पचास हजार करो□ रुप□ खर्च होंगे। यह रकम पछिले (2012) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है, जसिमें बयालीस हजार करो□ रुप□ खर्च हुआ थे। भारतीय लोकतंत्र का यह सबसे महंगा चुनावी दंगल है। इस बार चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा ब□। कर चौवन से सत्तर लाख रुप□ प्रति संसदीय सीट बांधी है, लेकिन जानकारों का दावा है कि ब□ दलों के प्रत्याशी लगभग दस करो□ रुप□ प्रति सीट लगाते हैं। प्रत्येक सीट पर अगर औसत चार दमदार प्रत्याशी जो□ जा□ तो देश भर की पांच सौ सैतालीस लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली रकम ही इक्कीस हजार करो□ रुप□ से ऊपर बैठेगी। पार्टी के ब□ नेताओं की चुनावी रैलियों पर व्यय होने वाला पैसा इससे अलग है। कउदाहरण से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अक्ते तमलिनाडु में पांच सौ से सात सौ के बीच चुनावी सभा□ हुरइं जनि पर करो□ों रुप□ फूँके ग□।

कले धन पर अंकुश लगाने के ल□ चुनाव आयोग प्रत्याशियों पर नजर रखता है, लेकिन उसे इस मुहमि में आंशकिसपलता ही मलि पाती है। फरि भी आयोग ने अरबों रुपया नकद और करो□ों रुप□ का सोना, चांदी और शराब पक□ी है। इस चुनाव पर आयोग और सरकार के भी सात-आठ करो□ रुप□ खर्च

होने का अंदाजा है। कुल मिला कर सोलहवीं लोकसभा के चुनावी महासमर में पछिली बार से तीन गुना अधिक पैसा लगेगा। भारतीय राजनीति में पैसे के बंधुते दुष्प्रभाव के कारण ही आज अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए चुनाव लड़ना और जीतना लगभग असंभव हो गया है। लोकसभा चुनाव में अब कानूनन अधिकतम खर्च की सीमा सत्तर लाख रुपए कर दी गई है। इतना पैसा गरीब तो क्या उच्च मध्यवर्ग का व्यक्ति भी पूरी जद्दगी नौकरी करने के बाद नहीं बचा पाता। ऐसे में वह चुनाव लड़ने की कल्पना भी कैसे कर सकता है? कॉरपोरेट फंडिंग ने रही-सही कसर पूरी कर दी है।

इस बार आम चुनाव में कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों का खुलेआम नाम लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो बात पहले कानों में कही जाती थी, इस बार चुनावी भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में अपनी एक जनसभा में मोदी के गुजरात के विकास मॉडल की खिल्ली उड़ते हुए उसे टॉफी-मॉडल बताया। बकैल राहुल, अडानी औद्योगिक समूह को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए मोदी ने टॉफी के मूल्य (एक रुपए प्रति गज) पर पैतालीस हजार का जमीन दे दी। टाटा कंपनी को नौ करोड़ का संयंत्र लगाने के लिए अनुचित मदद की।

जवाब में सुब्रहमण्यम स्वामी ने मोरचा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राबर्ट वडरा ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के नजदीक एक बेशकमती जमीन का 'लैंड यूज' बदलवा कर डीपीए के अर्बों रुपए का लाभ पहुंचाया। 'आप' के नेता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि तेलमंत्री वीरप्पा मोइली पश्चिमी घाट में इक्कीस बरस पहले हुई नीलामी की दर और शर्तों पर एक सप्ताह गुप्त के तेल और गैस कुएँ आबंटित करना चाहते हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के वरीध की अनदेखी कर तेलमंत्री उक्त कंपनी को बावन हजार करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

भाकपा सांसद ने चुनाव आयोग के पत्र लिख कर शकियत की कि उसने एक अप्रैल से प्रस्तावित गैस मूल्यवृद्धि पर रोक तो लगा दी, लेकिन रिलायंस समूह को लाभ पहुंचाने के लिए तेलमंत्री इस आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं। चुनाव के दौरान यह खबर भी आई कि हवा का रुख भांप कर बाकी संख्या में औद्योगिक घराने भाजपा और नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि अकेले मोदी की चुनावी रैलियों पर नौ से दस हजार करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो चुनावी उद्योगपति दे रहे हैं।

कांग्रेस खेमे ने खबर उड़ी कि चुनाव प्रचार के लिए उसके पास धन कम पड़ा गया है, जबकि धनूनासेठों की मेहरबानी से भाजपा पैसा पानी की तरह बहा रही है। इन सारी बयानबाजी से जनता ने यह जान लिया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ने के लिए बाकी पार्टियां कहां से पैसा जुटाती हैं और सत्ता में आने पर अपने चहेते उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचाती हैं।

कुछ समय पहले जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गैस घोटाले में मुकेश अंबानी और तेलमंत्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एक फफाफर दायर करने का आदेश दिया तो पूरे देश में हंगामा मच गया था। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने गैस घोटाले पर आज भी रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। इसी प्रकार जब केयला घोटाले में सीबीआई ने उद्योगपति कुमार मंगलम बाईला के दोषी मान उनके खिलाफ रिपोर्ट दायर कर जांच की बात कही तो कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता और उद्योग जगत बाईला के बचाव में उतर आया। उद्योगपतियों के वरिद्ध जांच के देश की आर्थिक सेहत और विकास के लिए हानिकारक बताया गया। जो पार्टियां कुछ माह पहले तक घोटालों में उद्योगपतियों का नाम आने पर उनका बचाव करती थीं, आज चुनावी सभाओं में खुलेआम उनका नाम क्यों घसीट रही हैं?

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पछिले दो दशक में देश की आर्थिक नीतियों में आया बदलाव और उसके परिणामों पर नजर डालनी होगी। 1991 में हमने मशीन अर्थव्यवस्था की डगर छोड़ी। खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्रेटा-परमिट राज खत्म हुआ। वैश्वीकरण और बाजार आधारित नीतियां अपनाने से विकास दर में खासा इजाफा हुआ। उद्योग-धंधे फले-फूले, भारी मात्रा में नवैश आया। विकास के साथ-साथ देश में आय का वितरण और

असमान हो गया। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का दौर चला, जिसकी कोख से कई घोटालों का जन्म हुआ। स्पेक्ट्रम, केयला और गैस के घोटालों में अरबों-खरबों रुपयों की हेराफेरी हुई।

सरकार ने नज्दी कंपनियों के लिए बाजार तो खोल दिया, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए न तो नियम-कयदे बना और न ही पारदर्शी नीतियां अपनाईं। रातोंरात मुनाफा कूटने की नीयत से कॉरपोरेट जगत के कुछ सूरमाओं ने राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं से नजदीकी रिश्ते बनाए। सत्ता के गलियारों में पैठ बनाने के लिए अनोखी जन-संपर्क नीतियां गयीं गईं। राडिया टेप से कॉरपोरेट जगत और सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच हुई दुरभसंधियों का पर्दाफाश हुआ।

मौजूदा राजनीति पर पैसे की कली परछाईं साफ देखी जा सकती है। राजनीति सेवा नहीं, पैसा कमाने का जरिया बन गई है। अब हर पार्टी और बड़े नेताओं के अपने-अपने उद्योगपति और कॉरपोरेट घराने हैं, जो उनके लिए चुनावों में खुले हाथ से पैसा पूंजते हैं। हवा का रुख भांप कर कुछ घराने पाला भी बदलते हैं। चंद बरस पहले तक सारा खेल परदे के पीछे होता था, अब खुल्लमखुल्ला होने लगा है। चुनावों पर कॉरपोरेट घरानों की राजनीतिक खेमेबंदी का असर दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। अगर कोई घराना किसी एक पार्टी का साथ देता है तो दूसरा दल उसका कच्चा चिट्ठा खोल देता है। यह काम सार्वजनिक मंच से होने लगा है।

स्वतंत्रता के बाद केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1947 से पहले कांग्रेस से जुड़े धननासेठों से सरकार का रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया। सेवा के बदले उन्हें मेवा भी खूब माला, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और कांग्रेस के दो पक्ष हो जाने से पुराने समीकरण गूँब गए। अधिकांश उद्योगपति मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ खड़े दिखे।

आम आदमी के लुभाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजा-महाराजाओं का प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। उनकी रणनीति सफल रही। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया और अपने वरिधियों को करारी शक्ति दी। इस चुनाव में उन्होंने वपिकी दलों के उद्योगपतियों का जैट कहा, लेकिन सीधे-सीधे किसी का नाम नहीं लिया।

जनसंघ के जमाने से भाजपा को बनियों और व्यापारियों की पार्टी माना जाता है। शुरू में उसके साथ मझोले उद्योगपति और व्यापारी ही जुड़े थे लेकिन केंद्र में वाजपेयी सरकार बनने के बाद उद्योग जगत में भाजपा ने गहरी पैठ बना ली। आज कांग्रेस के मुकबले भाजपा का कॉरपोरेट जगत में उतबा ज्यादा नजर आता है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, राहुल अडानी जैसे उद्योगपति भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। आम चुनाव में भाजपा ने जितना पैसा पूंज है वह कॉरपोरेट घरानों की मदद के बिना संभव नहीं है।

जिस हिसाब से चुनावी खर्च बढ़ रहा है उसे देख कर लगता है कि भविष्य में क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो जायेगा। बड़ी पार्टियां अपने धन के बल पर छोटे दलों को नगल जाँगीं। हमारे यहां भी यूरोपीय देशों और अमेरिका की तरह दो-तीन दल ही बचेंगे। यह व्यवस्था कॉरपोरेट जगत को भाती है। चुनदा दलों और नेताओं को साधना उनके लिए आसान होता है। ऐसी स्थिति में वे अपनी मर्जी से सरकार और नेताओं की अदला-बदली करते रहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में पूरा कॉरपोरेट जगत और मीडिया पार्टी लाइन पर बंटा हुआ है। जिसकी पार्टी जीत जाती है उसकी पौ बारह हो जाती है। हमारे देश में भी यह प्रवृत्ति शुरू हो चुकी है। अगर हालात नहीं बदले तो अगले चुनाव तक कॉरपोरेट खेमेबंदी और तेज हो जायेगी।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>